

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

प्रलिस के लयः

केंद्र प्रायोजतऱ योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शकषा अभयान ।

मेन्स के लयः

शकषा एवं संबंघतऱ योजनाएँ ।

चर्चा में क्यौं?

सरकार ने 'राष्ट्रीय उच्चतर शकषा अभयान' (RUSA) की योजना को 31 मार्च, 2026 तक या अगली समीकषा तक (जो भी पहले हो) जारी रखने की मंजूरी दे दी है ।

- इस प्रस्ताव में लगभग 12929.16 करोड़ रुपए का परवियय शामिल है, जसमें से केंद्र का हससा 8120.97 करोड़ रुपए और राज्य का हससा 4808.19 करोड़ रुपए होगा । योजना के नए चरण के तहत लगभग 1600 परयोजनाओं को समर्थन देने की परकिलपना की गई है ।

राष्ट्रीय उच्चतर शकषा अभयानः

- यह अक्तूबर 2013 में शुरु की गई केंद्र प्रायोजतऱ योजना है, जसका उद्देश्य पूरे भारत में उच्च शकषा संस्थानों को रणनीतक वतऱतपोषण प्रदान करना है ।
- केंद्रीय वतऱतपोषण (सामान्य श्रेणी के राज्यों के लयः 60:40 के अनुपात में, वशेष श्रेणी के राज्यों के लयः 90:10 के अनुपात में और केंद्रशासतऱ प्रदेशों के लयः 100%) मानदंड और परणाम आधारतऱ है ।
- इस कार्यक्रम के तहत वतऱतपोषण की राशा वशषिट संस्थानों तक पहुँचने से पूर्व राज्य सरकारों/केंद्रशासतऱ प्रदेशों के माध्यम से 'राज्य उच्च शकषा परिषदों' को प्रदान की जाती है ।
 - वभिन्न राज्यों को वतऱतपोषण 'राज्य उच्च शकषा योजनाओं' के मूल्यांकन के आधार पर कयऱ जाएगा, जो उच्च शकषा में समानता, पहुँच एवं उत्कृष्टता के मुदों को संबोधतऱ करने हेतु प्रत्येक राज्य की रणनीतका वर्णन करेगा ।

नए चरण में परकिलपनाः

- रूसा के नए चरण का लक्ष्य सुवधा से वंचतऱ क्षेत्रों, अपेक्षाकृत कम सुवधा वाले क्षेत्रों, दूरदराज/ग्रामीण क्षेत्रों, कठनऱ भौगोलकऱ स्थतऱ वाले क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावतऱ क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (एनईआर), आकांक्षी ज़िलों, द्वतऱतीय श्रेणी (टयऱर-2) के शहरों, कम जीईआर वाले क्षेत्रों आदऱतक पहुँच सथापतऱ करना और सतत् विकास लक्ष्यों का लाभ प्रदान करना है ।
- इस योजना के नए चरण को **नई शकषा नीतऱ** की उन सफऱरशऱओं और उद्देश्यों को लागू करने के लयः डज़ाइन कयऱ गया है, जो वर्तमान उच्च शकषा प्रणाली में कुछ महत्त्वपूर्ण बदलावों का सुझाव देते हैं ताकऱ प्रणाली में सुधार लाकर इसे फऱर से सक्रयऱ कयऱ जा सके और समानता एवं समावेशन के साथ गुणवत्तापूर्ण उच्च शकषा की सुवधा प्रदान की जा सके ।
- इस योजना के नए चरण के तहत लैंगकऱ समावेशन, समानता संबंधी पहल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगकऱ (आईसीटी), व्यावसायकऱ शकषा एवं कौशल उन्नयन के माध्यम से रोज़गार बढ़ाने के लयः राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाएगी ।
- राज्य सरकारों को नए मॉडल डगऱरी कॉलेज बनाने के लयः भी सहयोग दयऱ जाएगा ।
- बहु-वषऱक शकषा और अनुसंधान के लयः राज्य के वशऱवदऱयालयों को सहायता दी जाएगी ।
- भारतीय भाषाओं में सखऱने-सखऱने सहतऱ वभिन्न गतवऱधऱयऱओं के लयः मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त वशऱवदऱयालयों एवं कॉलेजों को मज़बूतऱ प्रदान करने के उद्देश्य से अनुदान प्रदान कयऱ जाएगा ।

उद्देश्यः

- राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में नरिधारति मानदंडों और मानकों के अनुरूप सुधार करना ।
- एक अनविार्य गुणवत्ता आशवासन ढाँचे (योग्यता का प्रमाणन) को अपनाना ।
- राज्य वशिवदियालयों में स्वायत्तता को बढावा देना और संस्थानों के शासन में सुधार करना ।
- संबद्धता, शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार सुनशिचति करना ।
- सभी उच्च शक्तिषण संस्थानों में गुणवत्ता युक्त संकायों की उपलब्धता और रोज़गार के सभी स्तरों पर कषमता नरिमाण सुनशिचति करना ।
- उच्च शक्तिषा प्रणाली में अनुसंधान के लयि एक सक्षम वातावरण बनाना ।
- उच्च शक्तिषा की पहुँच से अछूते कषेत्रों में संस्थानों की स्थापना कर कषेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना ।
- उच्च शक्तिषा के कषेत्र में वंचितों को पर्याप्त अवसर प्रदान कर इस कषेत्र में पक्षपात को समाप्त करना ।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rashtriya-uchchar-shiksha-abhiyan-2>

